



भारत में संविदा सरकार : एक सामयिक सिंहावलोकन

जितेन्द्र कुमार

शोधछात्र राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद .

प्रस्तावना :

भारतीय जनसंप्रभुता के प्राप्ति के उपरांत भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अंगीकार किया गया। लोकतंत्र राजतन्त्र के प्रतिकूल नागरिक जीवन पद्धति है। राजतन्त्र विवशता का दर्शन है तो लोकतंत्र जन्मसंभोगिता को सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र जन आकांक्षाओं की परिपूर्ति का माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति को अत्यान्तिक अनुभूति होती है कि वह शासन निर्माण की प्रक्रिया का आवश्यक एवं अपरिहार्य अघटक है। जन संवेदना लोकतंत्र की प्रत्याभूति है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकतंत्र सभ्य राज्यों की नीति और नियत बन गयी है, फलतः

विश्व ने उन्मुक्त हृदय से लोकतंत्र को जन वैधता प्रदान की है। सुदूर अतीत से लोकतंत्र मंथर गति से यात्रा करता हुआ अपनी गत्यात्मक उर्जा के साथ निरंतरता में विद्यमान है। भारत राज्य अपनी नागरिक जीवन प्रणाली में लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में आत्मसात कर रहा है। और इसकी जिजीविषा शक्ति में मात्रात्मक एवं गुणात्मक अभिवृद्धि हो रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा कच्छ से कामरूप तक प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र को प्रसन्न मन से तथा शुद्ध अंतःकरण से आत्मसात कर रहा है।

भारत राज्य का परिवेश एवं पर्यावरण जातीय नृजातीय धार्मिक एवं सांप्रदायिक दृष्टि से विविधता के अनेक स्वरूप को रूपायित करता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत में उत्तर भारत का विशाल हिंदी प्रदेश अपनी नागरिक चेतना से पृथक अस्मिता का निर्माण करता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत की नागरिक चेतना में विखंडन के तत्व विद्यमान नहीं रहते हैं। सामाजिक बिखराव के कारक तत्व जातीय नहीं प्रत्युत वर्गीय होता है। उत्तर भारतीय समाज शुद्ध भारतीय जातीय चेतना से परिनिर्मित होता है। उसमें समाज की अवरोधात्मक शक्तियां भी अनेक रूपों में अभिव्यक्ति पाती हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया के अनुसार भारतीय जाति की विशिष्टता होती है कि वह की प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपने से कनिष्ठ जाति की खोज कर लेता है तथा मनोवैज्ञानिक उच्चता निम्नता के कारक तत्वों को ढूढ़ लेता है। परिणामस्वरूप भारतीय

समाज में व्यापक विखंडन दृष्टि गोचर होता है ।
संभवतः इन्ही

तथ्यों को दृष्टि में रख कर गेलब्रेथ ने कहा था कि समाज की विवधता इसे नैसर्गिक लोकतान्त्रिक स्वरूप प्रदान करता है । संसदीय लोकतंत्र इस विविधता को संमेकित करने सद्प्रयास है । स्वतंत्रता के उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लगभग चार दशक भारतीय जन सत्ता के चंचल आकर्षण से सम्मोहित होते रहे हैं । कांग्रेस मुक्ति संग्राम की वाहिका थी । इसपर एक साथ तेलगु ,तमिल,मलयालम ,हिंदी भाषी तथा अनेक बोलियों एवं उपबोलियों के लोग एक स्वर में मतदान की प्रक्रिया से जुड़ते थे । इसका अभिलाभ मात्र कांग्रेस को मिलता था । विपक्ष जन समर्थन से दूर परिधि पर खड़ा रहता था। क्योंकि नागरिक मनोविज्ञान कांग्रेस से अपने सहज समीकरण को प्रतिस्थापित करते हुए इस आत्मबोध से तुष्ट होता था कि जिस कांग्रेस ने भारत वासियों को दाशता से विमुक्ति दिलाई है वही कांग्रेस भारत वासियों के निमित्त विकास के अवसरों की उपलब्धता करायेगी । ,लगभग दो दशक कांग्रेस भारत वासियों की अपेक्षा सपनों अकांक्षाओं का अभिकेन्द्र बनी रही ,इसी लिए प्रोफसर योगेन्द्र यादव कांग्रेस को पार्टी नहीं एक मंच मानते हैं जो भारत वाशियों में नागरिक संस्कार एवं शिल्पकार निर्माण करती थी ,कांग्रेस जब तक इस राजनैतिक जीवन शैली को अपनाती रही सत्ता उसकी परिधि बनती रही ,कांग्रेस का यह वैचारिक क्षितिज जैसे ही बिखरता है भारत राज्य में एक दल के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार का अवसान हो जाता है और भारत भारत का संसदीय लोकतंत्र मिलीजुली सरकारों के दौर में प्रवेश करता है । जिसने राजनितिक विश्लेषकों ने संविद सरकार की संज्ञा दी है । औपचारिक रूप से केरल में थानुपिल्लाई के नेतृत्व में प्रथम गैर कांग्रेसी संविद सरकार का निर्माण हुआ । थानुपिल्लाई के विधायक दल में साम्यवादी तथा मध्यवर्ती समाजवादी दल सम्मिलित थे । थानु पिल्लाई संयुक्त प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे। भारत में प्रथम संविद सरकार का प्रयोग सफल नहीं रहा क्योंकि इन दलों के पास न्यूनतम संयुक्त कार्यक्रम का आभाव था । विधायक दल में मतभेद से अधिक मनभेद तथा प्रतिस्पर्धा थी । संविद सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और सरकार की असामयिक मौत हो गयी।

भारत में मिली जुली सरकार का वास्तविक प्रारंभ १९७७ में जनता पार्टी की सरकार से होता है ,वहयतः जनता पार्टी की सरकार एक दल की सरकार प्रतीत होती है परन्तु अभ्यांतरिक दृष्टि से जनता पार्टी लोक दल, जन संघ तथा कांग्रेस से विक्षुब्ध हुए नेताओं का दल सम्मिलित था । वर्ष १९८९ में वी.पी .सिंह के नेतृत्व में रास्ट्रीय मोर्चे की सरकार पहली संविद सरकार है । भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक मतभेद साम्यवादी दल की असहमति मंदिर निर्माण का प्रश्न तथा जनता दल के नेताओं में अहम् के टकराव एवं सत्तालिप्सा ने रास्ट्रीय मोर्चा की सरकार का विखंडन कर दिया ,वी.पी.सिंह ने मंडल आयोग की संस्तुति को प्रवर्तन में ला दिया । भारत का समाज तनाव प्रतिरोध एवं समन्वय के नए युग में प्रवेश कर गया । पिछड़ा उभार एवं दलित चेतना के जागरण ने एक दल के नेत्रित्व में बहुमत की सरकार का तिलिस्म तोड़ दिया।,मिलीजुली सरकार संसदीय लोकतंत्र की शैली बन गयी ।यह भारतीय राजनैतिक इतिहास में गहरे विश्लेषण का यक्ष प्रश्न । अटल बिहारी वाजपेयी एवं मनमोहन सिंह की सरकार संविद सरकार का श्रेष्ठ सफल परीक्षण है । सरकार का निर्माण एवं संचालन क्रमशः दोनों दुस्कर कृत्य हैं । परन्तु अटल बिहारी वाजपेई एवं मनमोहन सिंह ने संतुलन के सूत्र को सफलता पूर्वक संचालित किया। संविद सरकार की विसंगतियों प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं सत्ता के शीर्ष पर दलों का प्रतिदावा नागरिक चेतना एवं नागरिक

सहनशक्ति को वरण करने योग्य नहीं लगा और भारत राज्य की जनता ने विखंडित जनादेश के स्थान पर वर्ष २०१४ में पंद्रहवी लोक सभा में स्पस्ट जनादेश का परिनिर्माण किया और संविद सरकार के परिवेश और पर्यावरण से भारत राज्य विमुक्त हुआ है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. मतदाताओं का संसार - प्रधान सम्पादक : अभय कुमार दुबे, भारतीय भाषा कार्यक्रम , वाणी प्रकाशन नई दिल्ली
2. भारत में राजनीतिक प्रक्रियायें - सम्पादक : बी एन चौधरी तथा युवराज कुमार
3. लोकतंत्र के सात अध्याय - सम्पादक : अभय कुमार -युवराज कुमार
4. रूलिंग आन नेशनल एंथम : प्रफुल्ल बिदवई, टाइम्स ऑफ़ इंडिया 18 से 29 अगस्त 1886
5. भारतीय राजनीतिक प्रणाली : यू आर घई
6. जाति परम्परा एवं इतिहास - सम्पादक : नीलकांत
7. जाति व्यवस्था, निरन्तरता एवं परिवर्तन : सुनील कुमार सिंह
8. भारतीय समाज : राम आहुजा
9. भारतीय राष्ट्रवाद की अधिनूतन प्रवृत्तियाँ : एस आर देसाई
10. आधुनिक भारत में विचारधारा और राजनीति : विपिन चन्द्र
11. भारत में राष्ट्रवाद एवं सांप्रदायिक राजनीति : मुशीरूल हशन
12. भारत में जाति प्रथा : जे एच हटन
13. सामाजिक न्याय लोकतंत्र और जाति व्यवस्था : रामगोपाल सिंह
14. भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन : एस एल दोषी